

गरवी गुजरात

PRGI No. GJHIN/26/A1393

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

वर्ष : 01
अंक : 043
दि. 15.11.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
SURAT EDITION

गुजरात में साढ़े तीन घंटे तक चला मोदी का मंथन, मंत्रियों को दिया जनसंपर्क और चुनावी तैयारी का मंत्र

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर शुक्रवार शाम राज्य के मंत्रियों के साथ हुई लंबी बैठक ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में 'डिनर डिप्लोमेसी' के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों की यादें ताजा करने के साथ मंत्रियों को सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने, जनता से सीधा संवाद करने तथा चुनाव से पहले जनसमर्थन मजबूत करने के कई अहम संदेश दिए। बातचीत का अंदाज औपचारिक बैठक से अलग रहा। प्रधानमंत्री ने हल्के-फुल्के माहौल में अपने राजनीतिक अनुभव साझा किए और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर से लेकर संगठन के विस्तार तक के कई प्रसंग सुनाए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री ने गुजरात की राजनीतिक यात्रा के पुराने पड़ावों को याद किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए किस तरह कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में काम किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद संगठन को गांव-गांव और समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों के जरिए मंत्रियों को यह समझाने की कोशिश की कि किसी भी राजनीतिक संगठन की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता और जनता के साथ उसका निरंतर जुड़ाव होता है। सत्ता में रहने के दौरान भी संगठन की जड़ों से जुड़े रहना और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है।

बैठक का एक प्रमुख केंद्र जनता से संपर्क और जनसमर्थन मजबूत करने का विषय रहा। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी कि वे केवल सरकारी बैठकों और प्रशासनिक कार्यक्रमों तक सीमित न रहें, बल्कि लगातार लोगों के बीच जाएं। आम नागरिकों की समस्याओं को सुनें, उनकी जरूरतों को समझें और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी राजनीति में जनता के बीच मौजूदगी का महत्व केवल चुनाव के समय नहीं होता, बल्कि पूरे कार्यकाल में लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाए रखना पड़ता



है। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनती है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह भी समझाया कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देता है, जब उनका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार योजनाएं तैयार हो जाती हैं और प्रशासनिक स्तर पर उनका क्रियान्वयन भी शुरू हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव या स्थानीय स्तर पर संपर्क की कमी के कारण पात्र लोगों तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। ऐसे में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी लें। लाभार्थियों से संवाद करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी सुविधाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ उनके प्रभाव का आकलन करने पर भी ध्यान देने की बात कही।

बातचीत के दौरान गुजरात में लागू की गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उनके परिणामों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि राज्य में शुरू की गई कई पहलों को बाद में देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया गया। उन्होंने मंत्रियों के साथ इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकती हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। गुजरात में शासन और संगठन के साथ काम करने के अपने पुराने अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाने और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम देने का संदेश दिया। बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में डिजिटल माध्यमों की बढ़ती भूमिका भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और नेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी है कि वे इस माध्यम से जनता के साथ जुड़े रहें। सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े फैसलों की जानकारी लोगों तक सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचाई जाए। डिजिटल माध्यम केवल प्रचार का साधन नहीं, बल्कि जनता से संवाद स्थापित करने और उनकी प्रतिक्रियाएं जानने का भी प्रभावी जरिया बन सकता है।

प्रधानमंत्री का यह सुझाव ऐसे समय में आया है, जब राजनीतिक दलों के लिए पारंपरिक जनसंपर्क के साथ डिजिटल उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। सोशल मीडिया पर सक्रियता, स्थानीय मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करने से जनप्रतिनिधियों की पहुंच बढ़ सकती है। हालांकि, डिजिटल संवाद के साथ वास्तविक जनसंपर्क बनाए रखना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की बातचीत में दोनों माध्यमों के संतुलित उपयोग का संदेश दिखाई दिया। बैठक में पुराने अनुभवों को साझा करने के साथ भविष्य की राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों को लेकर भी मार्गदर्शन दिया गया।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम कर्नाटक के मैसूर से अहमदाबाद पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे, जहां उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी। गुजरात दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों के साथ हुई लंबी बातचीत को राज्य की राजनीति और आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने गृह राज्य के नेताओं के साथ पुराने अनुभवों के माध्यम से यह संदेश दिया कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता के बीच निरंतर मौजूदगी किसी भी राजनीतिक सफलता के आधार हैं।

प्रधानमंत्री के दौरे का एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम शनिवार को प्रस्तावित अंबाजी मंदिर यात्रा का कार्यक्रम बदलना रहा। लाभ पंचम के अवसर पर प्रधानमंत्री का बनासकांठा जिले स्थित प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर जाने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन त्योहारों के मौसम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस दौरे को आगे के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया। मंदिर में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिदिन ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार को यह संख्या पांच लाख से भी अधिक होने की संभावना जताई गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात की अतिरिक्त व्यवस्था करने से आम श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती थी। वीवीआईपी दौरे के लिए सुरक्षा घेरे, मार्ग व्यवस्था और अन्य प्रोटोकॉल लागू करने पड़ते हैं। इससे मंदिर आने-जाने वाले भक्तों को प्रतीक्षा और असुविधा का सामना करना पड़ सकता था। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा टालने का निर्णय लिया गया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यह फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के कारण आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

अंबाजी मंदिर गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और इसे पवित्र शक्तिपीठ के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त है। यहां गुजरात के अलावा राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लाभ पंचम और त्योहारों के समय मंदिर में भक्तों की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और यातायात को सुचारु बनाए रखने की चुनौती रहती है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

मिशन 2027 की आहट के बीच लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, संगठन और सरकार की बढ़ेगी सक्रियता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने से लेकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर पार्टी का ध्यान केंद्रित है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को लखनऊ दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले कौशल दीक्षांत समारोह में देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास और युवाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का राजधानी पहुंचना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1500 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें लगभग 1000 विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के होंगे, जबकि करीब 200 विद्यार्थी दूसरे राज्यों से पहुंचेंगे। समारोह में 40 ट्रेड और छह जोन के टॉपर विद्यार्थियों में से चयनित लगभग 64 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश के छह विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विभिन्न ट्रेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। इस आयोजन के जरिए कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रयासों को भी प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह है कि अब तक कौशल



दीक्षांत समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है, लेकिन इस बार पहली बार इसे राष्ट्रीय राजधानी से बाहर लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में आयोजन राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे प्रदेश के आईटीआई संस्थानों और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के इस दौरे का समय भी राजनीतिक लिहाज से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। पार्टी नेतृत्व का जोर चुनाव से काफी पहले संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान पर भी ध्यान बढ़ाया है।

भाजपा की रणनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अलग-अलग भूमिकाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पार्टी की योजना के अनुसार प्रधानमंत्री बड़े क्षेत्रीय कार्यक्रमों और जनसभाओं के माध्यम से प्रदेश में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे, जबकि अमित शाह संगठनात्मक ढांचे, चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। आने वाले दिनों में अमित शाह के प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों का दौरा करने की तैयारी भी बताई जा रही है। इसके तहत संगठन के विभिन्न स्तरों पर बैठकें और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा सकती है। चुनाव से पहले भाजपा का जोर केवल बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं है। पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मतदाता सूची की जांच, नए मतदाताओं तक पहुंच और केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना रही है। संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दिए जाने की चर्चा है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही संगठनात्मक स्तर पर तैयारियों को व्यवस्थित कर लिया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री का लखनऊ दौरा केंद्रीय नेतृत्व की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता के क्रम में देखा जा रहा है।

पहाड़ी पर दीपम जलाने के विवाद में नया मोड़ सुप्रीम कोर्ट में HR&CE विभाग ने रखी दलील

मद्रास। पहाड़ी पर दीपम जलाने के स्थान को लेकर चल रहे विवाद में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर एंड सीई) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए हिंदू धर्म परिषद की याचिका का विरोध किया है। विभाग ने ऐतिहासिक अदालती फैसलों, मंदिर प्रशासन के अधिकारों और पुरातात्विक संरक्षण से जुड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि पहाड़ी के पूरे क्षेत्र का स्वामित्व या प्रशासन मंदिर अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंपने का आधार नहीं बनता। विभाग ने अदालत से याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने और याचिकाकर्ता पर मुकदमे का खर्च लगाने का अनुरोध किया है। एचआर एंड सीई विभाग ने अपने हलफनामे में वर्ष 1923 के दीवानी न्यायालय के फैसले और वर्ष 1931 में प्रिवी काउंसिल द्वारा उस फैसले को बहाल किए जाने का उल्लेख किया है। विभाग के मुताबिक, इन न्यायिक फैसलों में पहाड़ी के अधिकांश हिस्से का स्वामित्व मंदिर को दिया गया था, जबकि वहां स्थित मस्जिद और उससे जुड़े कुछ सीमित क्षेत्रों को मुस्लिम पक्ष के अधिकार में रखा गया था। विभाग का तर्क है कि इन फैसलों से पहाड़ी के अलग-अलग हिस्सों पर अधिकार और स्वामित्व की स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। इसलिए पुराने न्यायिक निर्णयों की अनदेखी कर पूरे पहाड़ी क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन करने की मांग स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। विभाग ने अपने पक्ष में वर्ष 1996 के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। हलफनामे के अनुसार, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि



दीपम सामान्य परिस्थितियों में पारंपरिक दीप मंडपम में ही मंदिर प्रशासन की ओर से जलाया जाएगा। किसी अन्य स्थान पर दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन का निर्णय और एचआर एंड सीई अधिकारियों की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। इसके साथ ही वैकल्पिक स्थान दरगाह, सीढ़ियों और नेल्लीथोप क्षेत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। विभाग का कहना है कि इस आदेश में दीपम जलाने की व्यवस्था और स्थान को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। एएसआई को पूरे मंदिर और पहाड़ी का नियंत्रण सौंपने की मांग पर भी विभाग ने आपत्ति जताई है। उसने वर्ष 1908 और 1909 की सरकारी अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें पहाड़ी के कुछ सीमित पुरातात्विक हिस्सों को ही संरक्षित घोषित किया गया था। इनमें चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा और शिलालेख जैसे ऐतिहासिक अवशेष शामिल थे। विभाग के अनुसार, इन अधिसूचनाओं में पूरी पहाड़ी को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में सीमित पुरातात्विक संरचनाओं के संरक्षण के आधार पर एएसआई को पूरे मंदिर और पहाड़ी के प्रशासन का अधिकार देने की मांग उचित नहीं है।

याचिका की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 32 का उल्लेख किया है। उसका कहना है कि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका तभी दाखिल की जा सकती है, जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। विभाग के मुताबिक, हिंदू धर्म परिषद ने ऐसा कोई मौलिक या कानूनी अधिकार स्थापित नहीं किया है, जिसके आधार पर अदालत मंदिर प्रशासन को उसकी पसंद के स्थान पर दीपम जलाने का निर्देश दे सके। विभाग ने यह भी दलील दी कि दीपम जलाने के स्थान से संबंधित विवाद पहले भी अदालतों के सामने उठ चुका है और इस विषय पर न्यायिक आदेश मौजूद हैं।

हलफनामे में वर्ष 2014 और 2017 में मद्रास हाईकोर्ट में हुई सुनवाई का भी उल्लेख किया गया है। विभाग के अनुसार, इन मामलों में पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। उसका तर्क है कि जब पहले से इस विषय पर न्यायिक विचार हो चुका है और मंदिर प्रशासन के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है, तो उसी मुद्दे को नए सिरे से उठाने के लिए ठोस कानूनी आधार होना चाहिए। विभाग ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को भी अदालत के सामने रखा है।

ईरान में फंसे भारतीय नाविक की स्वदेश वापसी का रास्ता खुला, मिला आपातकालीन प्रमाणपत्र

नई दिल्ली। ईरान में फंसे भारतीय नाविक अक्षय हरीश की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उन्हें आपातकालीन प्रमाणपत्र (इमरजेंसी सर्टिफिकेट) जारी कर दिया है। इसके बाद उनकी भारत वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अक्षय ने 9 नवंबर को तेहरान स्थित भारतीय मिशन से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई थी। भारतीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनी और जहाज के मालिक से संपर्क किया तथा जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की। अब उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अक्षय हरीश वर्ष 2025 में जापान से एक मर्चेंट जहाज पर सवार हुए थे। यह जहाज जब ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा, तो उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट और सीडीसी (कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) खो गया है। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें जहाज से उतार दिया गया। इसके बाद उनकी यात्रा और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया अटक गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय मिशन ने उनसे संपर्क स्थापित करने के बाद जहाज की कंपनी और मालिक से बातचीत की। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराए जाने के बाद अक्षय को आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किया गया है। यह दस्तावेज उनकी पहचान और भारत लौटने की प्रक्रिया में मददगार होगा।

विदेश मंत्रालय ने इस मामले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि विदेशों में कठिन परिस्थितियों में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय मिशन लगातार संबंधित देशों और संस्थाओं के संपर्क में रहते हैं। अक्षय के मामले में भी तेहरान स्थित भारतीय मिशन ने दस्तावेजी समस्या दूर करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ समन्वय किया। अब उनकी सुरक्षित और शीघ्र स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

इसी दौरान विदेश मंत्रालय ने आगामी 19वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की तैयारियों की भी जानकारी दी। यह सम्मेलन 7 से 9 जनवरी 2027 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रपति समापन सत्र में हिस्सा लेंगी। सम्मेलन का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों और देश के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। इसमें युवा प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के साथ निवेश, उद्यमिता, नवाचार और महिला सशक्तीकरण जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के जरिए प्रवासी भारतीयों को देश के विकास में भागीदारी के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर रहेगा। पाकिस्तान में आयोजित होने वाली चौथी अंतरराष्ट्रीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आमंत्रित किए जाने से जुड़े सवाल पर भी विदेश मंत्रालय ने भारत की नीति स्पष्ट की। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी देशों से जुड़े मामलों में भारत की राष्ट्रीय नीति का पालन करना आवश्यक है। किसी भी विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी मंत्रालय की समग्र नीति और संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। प्रवक्ता ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख का भी उल्लेख किया।

कुलगाम हमले के पीछे लश्कर मॉड्यूल का शक, मददगारों की तलाश में जुटीं एजेंसियां

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नाके पर हुए आतंकी हमले की जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस वारदात के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठित मॉड्यूल सक्रिय था, जिसमें स्थानीय आतंकी अब्दुल लतीफ के साथ दो पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका हो सकती है। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि हमले को अचानक अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि आतंकियों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। एजेंसियां अब हमलावरों के साथ-साथ उस स्थानीय नेटवर्क की तलाश में भी जुटी हैं, जिसने कथित तौर पर आतंकियों को पनाह देने, उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाने और वारदात के बाद सुरक्षित निकलने में मदद की।

11 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजकर 15 मिनट पर कुलगाम के अखरान इलाके में मीर बाजार के पास सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के नाके पर हमला किया गया था। आतंकियों ने एके राइफलों से अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। घायलों की पहचान हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंदू के रूप में हुई। सोमवीर सिंह के हाथ में और राकेश दास के पैर में गोली लगी थी, जबकि संतोष चंदू के पेट और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। घटना के तुरंत बाद तीनों जवानों को उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), अनंतनाग पहुंचाया गया।



बाद में संतोष चंदू की स्थिति और बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें श्रीनगर स्थित 92 बेस अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच शुरू की। शुरुआती स्तर पर आशंका जताई गई थी कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए होंगे, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद इस संभावना को लेकर जांच की दिशा में बदलाव आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, आतंकियों ने इलाके की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया। दलदली जमीन, घने पेड़ों और दुर्गम रास्तों के कारण सुरक्षा बलों के लिए उनका पीछा करना आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सीआरपीएफ नाके से करीब 50 मीटर की दूरी से गोलीबारी की और फिर आसपास के पेड़ों तथा कठिन रास्तों की आड़ लेकर मौके से फरार हो गए।

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने महज 15 सेकंड के भीतर एके राइफलों से करीब 30 राउंड गोलियां चलाईं। इतनी कम अवधि में अंधाधुंध फायरिंग कर भाग निकलने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावरों को नाके की स्थिति, वहां तैनात जवानों की गतिविधियों और आसपास के रास्तों की जानकारी पहले से कैसे मिली। इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि आतंकियों ने वारदात के लिए इसी स्थान और समय का चयन क्यों किया तथा हमले के बाद वे किस रास्ते से निकले।

सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन कारतूसों की जांच कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हथियारों और गोलियों से जुड़े सुराग जुटाना तथा यह पता लगाना है कि क्या बरामद कारतूसों का संबंध दक्षिण कश्मीर में हुई पिछली आतंकी वारदातों से भी हो सकता है। यदि कारतूसों के आधार पर किसी हथियार या पुराने मामले से समानता मिलती है तो जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, संदिग्ध गतिविधियों और घटनास्थल तक आने-जाने वाले संभावित रास्तों की भी पड़ताल की जा रही है।

इस पूरे मामले में अब स्थानीय मददगारों की भूमिका जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि आतंकियों को वारदात से पहले और बाद में स्थानीय स्तर पर सहायता मिली हो सकती है। इसी कड़ी में पिछले दो दिनों के दौरान 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। इनमें स्थानीय निवासी और ऐसे लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी गतिविधियां जांच के दायरे में आई हैं। पूछताछ के बाद अधिकतर लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि कम से कम 20 लोगों को आगे की जांच के लिए हिरासत में रखा गया है।

इन 20 संदिग्धों में से तीन लोगों पर लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि, अभी तक किसी की औपचारिक गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियां इन लोगों से पूछताछ कर उनके संपर्कों, गतिविधियों और संभावित भूमिका के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। जांचकर्ताओं को यह पता लगाना है कि क्या इन संदिग्धों ने आतंकियों को ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी, हमले से पहले सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखी थी या फिर वारदात के बाद उन्हें सुरक्षित निकलने में मदद की थी। आतंकवाद के खिलाफ अभियान में ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। ऐसे लोग प्रत्यक्ष रूप से हथियार लेकर हमले में शामिल नहीं होते, लेकिन आतंकियों को ठिकाना, भोजन, परिवहन, स्थानीय जानकारी और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका की आशंका रहती है। इसी वजह से जांच एजेंसियां केवल हमलावरों की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके सहारे आतंकी संगठन स्थानीय इलाकों में अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं।

भगवंत मान के लाहौर जाने पर सियासी घमासान, केंद्र की नीति के आगे अटकी यात्रा

चंडीगढ़/नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिलने के बाद भारत की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। 27 से 29 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित इस सम्मेलन में शामिल होने की मान की इच्छा पर अब केंद्र सरकार की अनुमति का सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत की मौजूदा राष्ट्रीय नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को राजनीतिक मंजूरी देना आसान नहीं होगा। मंत्रालय के रुख के बाद जहां आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की ओर से अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के पाकिस्तान जाने की इच्छा पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे विवाद में सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव की दलील के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत-पाकिस्तान संबंधों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया है।

भगवंत मान को लाहौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन 27 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। आयोजन से जुड़े निमंत्रण में पंजाब की साझा भाषा, साहित्य, संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर दोनों ओर के पंजाबी समाज के बीच संवाद बढ़ाने की बात कही गई है। इस निमंत्रण के बाद मुख्यमंत्री ने पंजाब विधानसभा में भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वे सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं। उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान के दोनों पंजाबों की ऐतिहासिक जड़ें, भाषा और सांस्कृतिक परंपराएं एक-द

चाय पर चर्चा

बच्चों को दीजिए अच्छे-बुरे की सीख

प्राय: कहा जाता है कि बच्चों की कोमल भावनाओं को समझना चाहिए। उन्हें ज्यादा रोकना-टोकना नहीं चाहिए। उनसे किसी बात के लिए न नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए ही काम करने वाले बहुत से संगठन इस पर जोर दे रहे हैं कि यदि आप बच्चे को न नहीं कहते तो उसे हमेशा हां सुनने की आदत पड़ जाती है। वे कभी न सुनना नहीं चाहते। घर में भी हमेशा बच्चों की मांगों को माना नहीं जा सकता, क्योंकि मांगों को पूरा करने में संसाधन और समय भी खर्च होता है। कोई जरूरी तो नहीं कि प्रत्येक परिवार के पास बच्चे की हर इच्छा पूरी करने के संसाधन और सामर्थ्य हों। फिर बच्चा हमेशा घर में तो रहता नहीं। स्कूल भी जाता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। बड़ा होकर नौकरी या अपना काम भी करता है। बच्चों के जीवन का यह चक्र बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यदि किसी बच्चे को बाहर निकलकर न सुनना पड़े तो उनका आत्मविश्वास हिल सकता है। वे अवसाद का शिकार हो सकते हैं। कई बार तो उनका स्वाभाविक विकास प्रभावित हो जाता है। अपने ही देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने अपनी जीवनी में लिखा है कि यदि संसाधन हों तो भी बच्चे को सही जिंदगी जीने का तरीका समझाने के लिए उसकी हर इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। उसे मेहनत और पैसे की बचत का महत्व समझाना चाहिए। आज के उपभोक्तावादी और प्रतिस्पर्धी युग में इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। बाहर की दुनिया उस कोमलता से भरी नहीं होती, जिसमें हां सुनने वाले तमाम बच्चे रह रहे होते हैं। वे बाहरी दुनिया का मुकाबला आसानी से कर सकें, इसके लिए समय-समय पर उनसे न कहना भी जरूरी है। यदि अपने यहां के पुराने पारिवारिक ढांचे को देखें तो वहां यही कहा जाता था कि यदि बच्चों को बिगाड़ना है तो उनकी हर जिद पूरी करो। यदि उन्हें जीवन जीने का सही तरीका समझाना है तो उनकी हर मांग पूरी न करें। बुजुर्गों की इन सीखों का समर्थन कई शोध भी कर रहे हैं। मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस से जुड़ी कई रिसर्च कहती हैं कि बच्चे का न सुनना उसके स्वस्थ दिमाग के विकास के लिए जरूरी है। जब बच्चे न सुनते हैं तो चाहे वे उस वक्त नाराज हों, पर इसके बारे में सोच-विचार भी करते हैं। अनेक मामलों में जिस बात के लिए न की गई होती है, वे दोबारा उसकी चर्चा नहीं करते। इन रिसर्च में यह भी कहा है कि बच्चों के सामने एक सीमा रेखा हमेशा खींचनी चाहिए। बच्चों को यह बताना जरूरी है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? यह जानना भी आवश्यक है कि माता-पिता या अन्य परिवार वालों के लिए उनकी कौन सी मांग पूरी करना संभव है और कौन सी नहीं? ऐसा करने से बच्चे धैर्यवान बनते हैं, दूसरे की इच्छा का सम्मान करना सीखते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए उन्हें अपनी जरूरत कितनी बढ़ानी है, इस पर भी विचार करते हैं। बच्चों में इतनी समझ होती है कि वे कम उम्र में ही वास्तविकता पहचान सकते हैं। जीवन और इस दुनिया की सच्चाई क्या है, वे इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। मनोविज्ञानियों ने इस बारे में कई उदाहरण दिए हैं। मान लीजिए एक बच्चा पार्क में खेल रहा है। अंधेरा घिर आया है। घर लौटने का समय हो गया, लेकिन बच्चा अभी और खेलना चाहता है। घर लौटने की बात पर वह रूठ जाता है। ऐसे में उससे कैसे न कहें कि वह दुखी भी न हो और अपनी सीमा को भी समझ जाए। इसका उदाहरण इस तरह दिया गया है, 'मुझे पता है कि तुम और खेलना चाहते हो और पार्क छोड़कर जाना तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन अब और नहीं खेला जा सकता। हमें घर जाना है। यह घर जाने का समय है।' इसी तरह यदि बच्चा कोई सामान लेने के लिए अड़ जाए तो कभी समझाकर, कभी कठोरता से न कहना पड़ता है। आजकल तो यह देखने में आता है कि माल या दुकान में खड़े होकर वह जो मांग रहा होता है, उसे माता-पिता खरीद देते हैं। ऐसा बच्चा कल ऐसा कुछ मांग सकता है, जिसे खरीदने के पैसे न हों या जो उसके लिए सही न हो, तब तो न कहना ही पड़ेगा। आजकल कई बार बच्चे मोबाइल फोन लेने के लिए अड़ जाते हैं। कई मां-बाप उन्हें दिला भी देते हैं, जबकि तमाम अध्ययन यही कह रहे हैं कि एक खास उम्र तक बच्चों के लिए मोबाइल हानिकारक है। इसलिए उनसे कहना ही पड़ेगा-तुम्हें अभी फोन नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे मनपसंद चीज न मिलने के कारण रोते हैं, सामान इधर-उधर फेंकने लगते हैं और खाना-पीना बंद कर देते हैं। अनेक माता-पिता बच्चों की ऐसी जिद के आगे झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा इस तरह रोएगा और कुछ खाएगा-पिएगा नहीं तो उसका कुछ नुकसान न हो जाए, जबकि यह एक तरह से अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों की ब्लैकमेलिंग होती है। यदि माता-पिता एक बार इस तरह उनके आगे झुक जाएं तो वे हमेशा अपनी बात पूरी कराने के लिए इसी तरह की जिद करेंगे। इसलिए बच्चों की हर जिद और मांग के आगे न झुकें। बच्चे की हर शिकायत को सही न मानकर उसके अच्छे-बुरे पर भी विचार करें। चाहे बच्चे की मंशा गलत न हो, मगर कई बार वे बहाने भी बनाते हैं। खुद के बचाव के लिए दूसरों का नाम भी लेते हैं। दरअसल छुटपन में वे व्यवहार के बहुत से तरीके सीखते हैं।

चीन की पकड़ से मुक्त होने के लिए भारत को मजबूत करनी होगी अपनी आपूर्ति श्रृंखला

भारत को यह भी समझना होगा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ हर चीज का उत्पादन देश के भीतर करना नहीं है। जिन संसाधनों की उपलब्धता दूसरे देशों में अधिक है, उनके लिए विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बनाना भी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अन्य संसाधन संपन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार कर सकता है।



वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश की ताकत केवल उसके आर्थिक आकार, सैन्य क्षमता या तकनीकी विकास से तय नहीं होती, बल्कि उन संसाधनों पर उसके नियंत्रण से भी निर्धारित होती है, जिनके बिना आधुनिक उद्योगों का संचालन संभव नहीं है। आज रेयर अर्थ तत्व ऐसे ही रणनीतिक संसाधन बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, स्मार्टफोन और पवन ऊर्जा संयंत्रों तक इनकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इनकी आपूर्ति पर चीन का लगभग एकाधिकार पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। चीन जब चाहे अपनी निर्यात नीति में बदलाव करके दूसरे देशों के औद्योगिक उत्पादन और रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। हाल में निर्यात प्रतिबंधों पर लगी अंतरिम रोक को दो महीने आगे बढ़ाने का उसका निर्णय इसी वास्तविकता को उजागर करता है। भारत के लिए यह समय केवल राहत महसूस करने का नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी करने का है।

गत नौ नवंबर को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि कुछ निर्यात प्रतिबंधों पर लागू अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दी जाएगी। इस फैसले से दुनिया के कई देशों के उद्योगों को फिलहाल राहत मिली है। जर्मनी, जापान, भारत और अमेरिका जैसे देशों में वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रक्षा उपकरणों से जुड़े उद्योगों को अपनी उत्पादन गतिविधियां जारी रखने का अवसर मिला है। हालांकि इस घोषणा को चीन की ओर से स्थायी राहत नहीं माना जा सकता। प्रतिबंध समाप्त नहीं किए गए हैं, बल्कि उनके प्रभावी होने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाला गया है। इसका मतलब है कि चीन के पास भविष्य में फिर से निर्यात नियंत्रण लागू करने का विकल्प मौजूद है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में रेयर अर्थ तत्व हैं। रेयर अर्थ 17 धात्विक तत्वों का समूह है, जिनका आधुनिक तकनीक और औद्योगिक उत्पादन में विशेष महत्व है। इनके नाम से भले ही इनके अत्यंत दुर्लभ होने का संकेत मिलता हो, लेकिन वास्तविक समस्या इनका उपलब्ध होना नहीं, बल्कि इन्हें दूसरे पदार्थों से अलग करना और उपयोग योग्य रूप में परिष्कृत करना है। खनन के बाद इन तत्वों को अलग करने और शुद्ध करने की प्रक्रिया काफी जटिल, महंगी और पर्यावरण के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। इसके लिए विशेष तकनीक, भारी निवेश और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

परिष्कृत रेयर अर्थ तत्वों का इस्तेमाल बेहद शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। आकार में छोटे होने के बावजूद ये चुंबक अत्यधिक क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों, पवन ऊर्जा टर्बाइनों, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, स्मार्टफोन, लड़ाकू विमानों और निर्देशित मिसाइलों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक रक्षा प्रणालियों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी इनकी आवश्यकता होती है। इनका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि किसी कारखाने को संचालित करने के लिए हजारों पुर्जों की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से एक छोटा-सा चुंबक भी समय पर उपलब्ध न हो तो पूरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

रेयर अर्थ की वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में चीन की स्थिति सबसे मजबूत है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2024 में चुंबक निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ तत्वों के खनन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत थी। परिष्करण के क्षेत्र में यह हिस्सेदारी करीब 91 प्रतिशत और तैयार चुंबकों के उत्पादन में लगभग 94 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसी भारी दुर्लभ धातुओं के उत्पादन और परिष्करण में चीन का वर्चस्व और भी अधिक है। इन तत्वों की खासियत यह है कि ये चुंबकों को अत्यधिक तापमान में भी अपनी क्षमता बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि रक्षा उपकरणों और उच्च तकनीक वाले औद्योगिक उत्पादों में इनकी मांग लगातार बनी रहती है।

सवाल यह है कि जब रेयर अर्थ के भंडार दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं तो चीन का इतना बड़ा दबदबा कैसे स्थापित हो गया? इसका जवाब उसकी दीर्घकालिक औद्योगिक नीति में छिपा है। चीन ने पिछले चार दशकों में खनन, परिष्करण और चुंबक निर्माण की पूरी व्यवस्था विकसित करने पर भारी निवेश किया। उसने उत्पादन लागत कम रखने, तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने और वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया। दूसरी ओर, पर्यावरणीय नुकसान और भारी निवेश की चुनौतियों के कारण कई देशों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता विकसित नहीं की। परिणामस्वरूप चीन धीरे-धीरे पूरी आपूर्ति श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अप्रैल 2025 में चीन ने कुछ चुनिंदा रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर नियंत्रण लागू करते हुए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में उसने इन प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाने की घोषणा की। इसमें औद्योगिक उपयोग से जुड़ी अन्य सामग्रियों और तकनीकों को भी शामिल किया गया। बाद में दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बनी सहमति के बाद इन प्रतिबंधों को फिलहाल टालने का निर्णय हुआ। नौ नवंबर की घोषणा उसी अंतरिम व्यवस्था को आगे बढ़ाने से संबंधित है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि रेयर अर्थ अब केवल औद्योगिक कच्चा माल नहीं रह गए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने का प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं। चीन की इस नीति के पीछे कई रणनीतिक उद्देश्य दिखाई देते हैं। पहला उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अपनी स्थिति मजबूत करना है। जब किसी महत्वपूर्ण उत्पाद की वैश्विक आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा एक ही देश के नियंत्रण में हो तो वह निर्यात लाइसेंस और अन्य शर्तों के माध्यम से दूसरे देशों पर दबाव बना सकता है। दूसरा उद्देश्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तकनीकी पाबंदियों का जवाब देना है। सेमीकंडक्टर, अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में चीन को जिन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, उनके जवाब में वह अपने नियंत्रण वाले संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा उद्देश्य वैश्विक औद्योगिक व्यवस्था में अपनी रणनीतिक स्थिति बनाए रखना है। चीन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि महत्वपूर्ण तकनीकी उद्योगों के लिए दुनिया उसकी आपूर्ति पर निर्भर बनी रहे।

इस रणनीति का उदाहरण वर्ष 2010 में भी देखने को मिला था, जब क्षेत्रीय विवाद के दौरान चीन ने जापान को रेयर अर्थ की आपूर्ति प्रभावित कर दी थी। उस समय जापानी उद्योगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस घटना ने दुनिया को पहली बार गंभीरता से समझाया कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता किस तरह आर्थिक और रणनीतिक कमजोरी बन सकती है। इसके बावजूद अनेक देशों ने वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई।

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। इन सभी क्षेत्रों में रेयर अर्थ चुंबकों की जरूरत बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ चुंबकों का आयात किया और इसमें चीन की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक रही। इस निर्भरता के कारण चीन की निर्यात नीति में होने वाला कोई भी बदलाव भारतीय उद्योगों की लागत, उत्पादन और विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

विडंबना यह है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में कमजोर नहीं है। देश में लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड के बराबर भंडार होने का अनुमान है। इस आधार पर भारत दुनिया के प्रमुख रेयर अर्थ संसाधन संपन्न देशों में शामिल है। इसके बावजूद घरेलू उत्पादन और परिष्करण की क्षमता सीमित है। वर्ष 2024 में भारत का रेयर अर्थ उत्पादन लगभग 2,900 टन रहा, जो वैश्विक उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ है कि हमारे पास संसाधन मौजूद होने के बावजूद उन्हें औद्योगिक उपयोग के योग्य बनाने की व्यवस्था पर्याप्त विकसित नहीं हो पाई है।

सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशों में खनिज संसाधनों तक पहुंच बनाने के प्रयास भी आवश्यक हैं। लेकिन केवल योजनाओं की घोषणा से आत्मनिर्भरता हासिल नहीं होगी। इसके लिए दीर्घकालिक निवेश, आधुनिक तकनीक, शोध संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना होगा।

भारत को यह भी समझना होगा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ हर चीज का उत्पादन देश के भीतर करना नहीं है। जिन संसाधनों की उपलब्धता दूसरे देशों में अधिक है, उनके लिए विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बनाना भी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अन्य संसाधन संपन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार कर सकता है। इसके साथ ही जहां घरेलू स्तर पर खनन और उत्पादन की संभावनाएं हैं, वहां निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। रेयर अर्थ के परिष्करण और स्थायी चुंबकों के निर्माण में विशेष सब्सिडी, तकनीकी सहायता तथा उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैटरियों और औद्योगिक मशीनों से उपयोगी खनिजों को पुनः प्राप्त करने की तकनीक पर भी ध्यान देना होगा। इससे आयात पर दबाव कम किया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। खनन और परिष्करण के दौरान पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है, क्योंकि विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। चीन की ओर से मिली दो महीने की मोहलत को भारत के लिए चेतावनी और अवसर दोनों के रूप में देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आज जो देश अपनी आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, वही भविष्य में दूसरे देशों की औद्योगिक गति को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। भारत को ऐसी स्थिति से बचने के लिए अभी से मजबूत घरेलू क्षमता विकसित करनी होगी और भरोसेमंद वैश्विक साझेदारियों का विस्तार करना होगा। वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब देश के पास महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता के साथ उन्हें उपयोगी उत्पादों में बदलने की तकनीक और क्षमता भी हो। चीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी अब विकल्प नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा और सामरिक मजबूती की अनिवार्य जरूरत बन चुकी है।

टेक्नॉलॉजी

घर की सुरक्षा अब स्मार्ट तकनीक के हवाले, सीसीटीवी के अलावा भी हैं कई विकल्प

बदलती जीवनशैली और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच घर की सुरक्षा हर परिवार की प्राथमिकता बनती जा रही है। नौकरी, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी कामों के कारण लोगों को दिन का अधिकांश समय घर से बाहर बिताना पड़ता है। कई बार परिवार छुट्टियों पर बाहर जाता है या किसी जरूरी काम से कई दिनों तक दूसरे शहर में रहना पड़ता है। ऐसे में घर खाली रहने के दौरान चोरी, अनधिकृत प्रवेश और अन्य अप्रिय घटनाओं की आशंका बनी रहती है। घर में बुजुर्गों और बच्चों की मौजूदगी होने पर उनकी सुरक्षा की चिंता भी परिवार के सदस्यों को परेशान करती है। पहले घर की सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजे, ताले और चौकीदार पर निर्भरता रहती थी, लेकिन अब तकनीक ने सुरक्षा के नए रास्ते खोल दिए हैं। स्मार्ट होम सिक्योरिटी गैजेट्स की मदद से घर की निगरानी करना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्राप्त करना आसान हो गया है।

आज बाजार में ऐसे अनेक आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जो घर की सुरक्षा को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाते हैं। स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे, वीडियो डोरबेल, डिजिटल डोर लॉक, मोशन सेंसर, डोर सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम इनमें प्रमुख हैं। इन उपकरणों की खासियत यह है कि इन्हें मोबाइल फोन और इंटरनेट से जोड़कर कहीं से भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि घर के दरवाजे पर कोई अनजान व्यक्ति आता है या किसी कमरे में असामान्य गतिविधि होती है तो मोबाइल पर तत्काल सूचना मिल सकती है। इस तरह घर से दूर रहने के बावजूद परिवार को अपने घर की स्थिति की जानकारी मिलती रहती है।

आधुनिक होम सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अलग-अलग उपकरण एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर लगा सेंसर किसी के प्रवेश का संकेत देता है, कैमरा उस गतिविधि की तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करता है और अलार्म सिस्टम जरूरत पड़ने पर चेतावनी जारी कर सकता है। इससे सुरक्षा केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था भी तैयार होती है। घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट कैमरों ने इनकी उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। पहले कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के लिए निर्धारित स्थान पर मौजूद रहना पड़ता था, जबकि अब इंटरनेट से जुड़े कैमरों को मोबाइल एप के माध्यम से कहीं से भी देखा जा सकता है। इनमें लाइव वीडियो, नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन और रिकॉर्डिंग दोबारा देखने जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

कुछ कैमरों में व्यक्ति की पहचान करने और सामान्य गतिविधियों तथा संदिग्ध हलचल के बीच अंतर करने की तकनीक भी उपलब्ध है। घर के मुख्य दरवाजे, पार्किंग, बरामदे और पीछे के प्रवेश द्वार पर इन्हें लगाना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, कैमरे ऐसी जगह लगाने चाहिए, जहां से घर की सुरक्षा सुनिश्चित हो और परिवार के सदस्यों की निजी जिंदगी प्रभावित न हो।

वीडियो डोरबेल आधुनिक घरों के लिए उपयोगी सुरक्षा उपकरण बनकर उभरी है। इसे मुख्य दरवाजे के बाहर लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति घंटी बजाता है या दरवाजे के सामने आता है तो घर के सदस्य मोबाइल फोन पर उसका वीडियो देख सकते हैं। कई उपकरणों में दोतरफा बातचीत की सुविधा भी होती है। इसका अर्थ है कि घर में मौजूद न होने पर भी व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़े मेहमान या डिलीवरी कर्मचारी से बात कर सकता है। कुछ मॉडल मोशन सेंसर और नाइट विजन के साथ आते हैं, जिससे रात के समय भी दरवाजे के आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिलती है। बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों के लिए यह उपकरण विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उन्हें बिना पहचान किए किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

घर की सुरक्षा में दरवाजे का लॉक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक तालों में चाबी खोने, चोरी होने या उसकी दूसरी चाबी तैयार कराए जाने जैसी समस्याएं रहती हैं। स्मार्ट डोर लॉक इन परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इनमें फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, पिन कोड, कार्ड और मोबाइल एप के माध्यम से दरवाजा खोलने की सुविधा मिलती है। कुछ उपकरणों में अस्थायी एक्सेस कोड भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें किसी मेहमान या अधिकृत कर्मचारी के साथ सीमित समय के लिए साझा किया जा सकता है। इससे घर के सदस्यों के आने-जाने का प्रबंधन आसान होता है। कुछ स्मार्ट लॉक दरवाजा खुलने और बंद होने की सूचना भी मोबाइल पर भेजते हैं। हालांकि, इन्हें खरीदते समय आपातकालीन चाबी, बैटरी बैकअप और मैनुअल अनलॉक की सुविधा जरूर देखनी चाहिए।

मोशन सेंसर घर की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका काम किसी निर्धारित क्षेत्र में होने वाली हलचल का पता लगाना है। यदि घर खाली है और किसी कमरे में अचानक गतिविधि होती है तो सेंसर सुरक्षा सिस्टम को संकेत भेज सकता है। इसके बाद मोबाइल पर अलर्ट प्राप्त हो सकता है या इससे जुड़े अलार्म की आवाज सुनाई दे सकती है। इन सेंसरों को मुख्य प्रवेश द्वार, गलियारे, सीढ़ियों और उन कमरों में लगाया जा सकता है, जहां की निगरानी जरूरी हो। कुछ आधुनिक सेंसर पालतू जानवरों की सामान्य गतिविधियों को नजरअंदाज करने के लिए भी तैयार किए जाते हैं। हालांकि, इन्हें सही स्थान पर लगाना जरूरी है, ताकि हवा, तापमान या अन्य सामान्य गतिविधियों के कारण बार-बार गलत अलर्ट न आएं। घर के दरवाजों और खिड़कियों की सुरक्षा के लिए डोर और विंडो सेंसर उपयोगी विकल्प हैं। इनमें आमतौर पर दो छोटे हिस्से होते हैं, जिन्हें दरवाजे या खिड़की के फ्रेम पर लगाया जाता है। जैसे ही दरवाजा या खिड़की खुलती है, दोनों हिस्सों के बीच संपर्क टूट जाता है और सेंसर अलर्ट भेज देता है।

विचार प्रवाह

सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम घोषित, दो दिसंबर को होगी परीक्षा

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने कॉन्स्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन, कॉन्स्टेबल फायर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए परीक्षा दो दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने का अवसर मिल गया है। उम्मीदवार अब निर्धारित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी के साथ जरूरी दस्तावेजों और अन्य व्यवस्थाओं को भी समय रहते पूरा कर सकते हैं।

सीआईएसएफ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार परीक्षा देशभर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या और परीक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसका आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा का समय एक जैसा होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा तिथि, शिफ्ट और केंद्र से संबंधित विस्तृत जानकारी उसके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार महत्वपूर्ण हो गया है।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से सीआईएसएफ में कुल 3,415 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन के 1,161 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं कॉन्स्टेबल फायर के 1,130 पदों और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 1,124 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तीनों श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों की जानकारी विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से मिलती रहेगी। भर्ती का उद्देश्य सीआईएसएफ के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद अब उम्मीदवारों की निगाहें एडमिट कार्ड जारी होने पर टिकी हैं। सीआईएसएफ की ओर से प्रवेश पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की निश्चित तारीख की जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें। प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित प्रमाणिक जानकारी के लिए केवल सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण से जुड़ी जानकारी, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। यदि नाम, जन्मतिथि या अन्य किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि संबंधित विभाग से समय रहते संपर्क करना चाहिए। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट के होमपेज पर जाना होगा। वहां उपलब्ध एडमिट कार्ड या भर्ती से संबंधित सेक्शन को खोलना होगा। इसके बाद 'CISF Constable Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक खुलने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित स्थान पर अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी। जानकारी सबमिट करते ही प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंट भी निकाल लें। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले कुछ जरूरी तैयारियां भी पूरी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते को अच्छी तरह देख लें। यदि केंद्र दूसरे शहर या दूरस्थ क्षेत्र में है तो वहां पहुंचने की योजना पहले से बना लें। परीक्षा के दिन रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचना बेहतर रहेगा, ताकि यातायात या अन्य किसी कारण से देरी होने पर परेशानी न हो। इसके अलावा प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा-निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर कौन-से पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज ले जाने की अनुमति है, इसकी जानकारी आधिकारिक निर्देशों से प्राप्त कर लें।

परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों को बचे हुए समय का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। जिन विषयों और टॉपिक की तैयारी अभी अधूरी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। पहले से पढ़े गए विषयों का नियमित दोहराव करें और अभ्यास के लिए प्रश्नपत्रों तथा मॉक टेस्ट की मदद लें। समयबद्ध तरीके से प्रश्न हल करने का अभ्यास करने से परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।

फैक्ट ऑफ द डे

जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल बड़े शहरों, राजमहलों और राजनीतिक आंदोलनों तक सीमित नहीं है। देश के जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में भी आजादी की ऐसी अलख जगी थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस संघर्ष के महानायक थे बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासी समाज श्रद्धा से भगवान और 'धरती आबा' के नाम से पुकारता है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में वह साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का परिचय दिया, जिसकी मिसाल आज भी देश के इतिहास में सम्मान के साथ दी जाती है। उनका संघर्ष केवल अंग्

छठ पर बिहार में साफ रहेगा मौसम, दिल्ली-यूपी में बूंदाबांदी के आसार, पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ

नई दिल्ली। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में देशभर के मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि कई इलाकों में कोहरे की चादर दिखाई देने लगी है। दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। इस बीच छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को बिहार के सभी 38 जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छा सकता है। ऐसे में छठ पूजा के दौरान मौसम की स्थिति को लेकर लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के 15 राज्यों के लिए मौसम को लेकर अलग-अलग पूर्वानुमान जारी किया है।

राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण दिन के तापमान में हल्का बदलाव हो सकता है, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 16 नवंबर से 20 नवंबर तक सुबह के समय मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार और सोमवार को हल्की बारिश अथवा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव के साथ तापमान में उतार-



चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 और 17 नवंबर को प्रदेश के दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने से हाईवे और प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी होगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रात और सुबह की ठंड धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

बिहार में छठ पर्व के अवसर पर मौसम के शुष्क रहने का अनुमान श्रद्धालुओं के लिए राहत भरा है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छा सकता है। छठ पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसे में मौसम साफ रहने से पूजा की तैयारियों और धार्मिक गतिविधियों में सुविधा रहने की उम्मीद है। सुबह के समय हल्की ठंड और कोहरे का असर रह सकता है, इसलिए घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को गर्म कपड़ों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। बिहार में मौसम शुष्क रहने के बावजूद सुबह और रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास बढ़ सकता है।

झारखंड में भी रविवार को अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य में बारिश की संभावना कम है, जबकि सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 नवंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं ओडिशा में 18 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इन राज्यों में मौसम की गतिविधियां स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रह सकती हैं। पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां सुबह की ठंड बढ़ रही है, वहीं कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

राजस्थान में भी मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने रविवार को बीकानेर और जयपुर संभाग के 10 जिलों में बादल छाने तथा कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में मौसम बदलने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार पारा गिरने से ठंड का असर बढ़ रहा है। खासकर सुबह और रात के समय तापमान में कमी महसूस की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में सर्द हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर ठंड का प्रभाव बढ़ सकता है।

दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 15 से 20 नवंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में 19 और 20 नवंबर को बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 17 और 18 नवंबर के साथ 20 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में 18 से 20 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने की जरूरत होगी।

पहाड़ी राज्यों में मौसम का असर और अधिक दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड के पांच जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रविवार को बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के 3,200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं निचले क्षेत्रों में बादल छाए रहने और ठंड बढ़ने का असर दिखाई दे सकता है। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही निकलने की जरूरत है।

हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में बारिश हो सकती है, जबकि जनजातीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने का अनुमान है। निचले इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ों पर मौसम में बदलाव का असर पर्यटन और आवागमन पर भी पड़ सकता है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर सकता है और कुछ मार्गों पर फिसलन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर नवंबर के दूसरे पखवाड़े में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की अलग-अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। बिहार में छठ पर्व के दौरान मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, जबकि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में बादल और बूंदाबांदी के आसार हैं तो मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है। दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहने तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है। उत्तर भारत में कोहरे की बढ़ती मौजूदगी भी आने वाले दिनों में सर्दी के प्रभाव को और स्पष्ट कर सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को स्थानीय पूर्वानुमान और चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी है, क्योंकि मौसम की स्थिति में क्षेत्रवार बदलाव संभव है।

कोटा की डेयरी में गैस जलाते ही भड़की आग, कर्मचारी की दर्दनाक मौत

कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसे में चाय बनाने के लिए गैस जलाते ही दुकान में भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दुकान में काम कर रहा एक कर्मचारी अंदर ही फंस गया और गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौत हो गई। हादसा भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र में स्टेशन राम मंदिर की गली स्थित मधुर डेयरी में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुकान में रखे गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था। कर्मचारी ने जैसे ही चाय बनाने के लिए गैस जलाई, अचानक आग भड़क उठी और उसे बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कर्मचारी बुरी तरह झुलस चुका था।

जानकारी के अनुसार, मधुर डेयरी की दुकान करीब 10×12 फीट की थी। दुकान में चाय, गुटखा, सिगरेट और अन्य दैनिक उपयोग का सामान रखा हुआ था। शनिवार शाम करीब 6 बजकर 40 मिनट पर दुकान पर काम करने वाला लेखराज चाय बनाने के लिए गैस जलाने पहुंचा। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण दुकान के भीतर गैस जमा हो गई थी। जैसे ही उसने गैस जलाई, आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। कुछ ही पलों में लपटें दुकान के अंदर फैल गईं और वहां रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया।



हादसे के समय दुकान में धनराज और प्रेम शंकर भी मौजूद थे। आग भड़कते ही दोनों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन लेखराज दुकान के भीतर ही फंस गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसे बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। आसपास मौजूद लोगों ने भी उसे बचाने और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। छोटी दुकान में सामान भरा होने के कारण अंदर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई और आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के दमकल विभाग को जानकारी दी गई। नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के अनुसार, शाम करीब 6:40 बजे मधुर डेयरी में गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के लगभग 10 मिनट के भीतर दमकल की तीन गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की लपटें तेज होने के कारण शुरुआती दौर में काफी कठिनाई आई, लेकिन लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

आग बुझने के बाद दमकलकर्मी और भीमगंजमंडी थाना पुलिस दुकान के अंदर पहुंचे। वहां लेखराज गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में मिला। उसे तत्काल एंबुलेंस की मदद से एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जिस दुकान में लेखराज पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, वहीं उसका जीवन समाप्त हो गया।

आसपास के दुकानदारों के मुताबिक, दुकान में रखे गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था। हालांकि, रिसाव की स्थिति का आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना अभी बाकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही लेखराज ने चाय बनाने के लिए गैस जलाई, अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पड़ोसियों ने तत्काल अग्निशमन यंत्र और पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटों की तीव्रता के सामने उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई।

पास के रेस्टोरेंट के संचालक मोनी मखीजा ने बताया कि मधुर डेयरी पिछले करीब 15 वर्षों से संचालित हो रही है। लेखराज पिछले लगभग तीन वर्षों से इस दुकान पर काम कर रहा था। वह नियमित रूप से दुकान के कामकाज में हाथ बंटाता था। हादसे के समय दुकान के मालिक विनोद अग्रवाल बाजार गए हुए थे। आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम जुट चुकी थी और लेखराज को अस्पताल ले जाया जा चुका था।

मृतक की पहचान लेखराज पुत्र रामविलास, निवासी भदाना, कोटा के रूप में हुई है। घटना ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। रोजमर्रा की तरह दुकान पर काम करने पहुंचे लेखराज के साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुकान के भीतर मौजूद दो अन्य लोगों के समय रहते बाहर निकल आने से उनकी जान बच गई, लेकिन लेखराज आग की चपेट में आने के कारण बाहर नहीं निकल सका।

फिलहाल भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों, गैस सिलेंडर की स्थिति और दुकान में सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल कर रही है। यह भी जांच की जाएगी कि गैस पाइप, रेगुलेटर और सिलेंडर में किसी तरह की खराबी या रिसाव तो नहीं था। जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

श्रीगंगानगर रेल ट्रैक धमाके में दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, महिला भी शामिल

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेल ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और श्रीगंगानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब पुलिस के सहयोग से गुरदासपुर में दबिश देकर दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय महिला महकदीप कौर और 23 वर्षीय देवेंद्र सिंह शामिल हैं। दोनों पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इस मामले में महिला आरोपी के कब्जे से दो हथियार, 46 कारतूस और विस्फोट की वारदात को अंजाम देने के लिए दिए गए 30 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। घटना के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका होने की आशंका के चलते जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एजेंसियां पाकिस्तान कनेक्शन के पहलू से भी पड़ताल कर रही हैं।

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) दिनेश एमएन खुद गुरदासपुर पहुंचे। उन्होंने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त अभियान की निगरानी की। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई के बाद आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। इस अभियान में



एएसपी श्रीगंगानगर नितिन चौधरी, एएसपी एटीएस मनीष शर्मा और एएसपी एटीएस सुरेंद्र सिंह भी शामिल रहे।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह की भूमिका श्रीगंगानगर रेल ट्रैक विस्फोट मामले में सामने आई है। हालांकि, वारदात में दोनों की भूमिका का पूरा ब्योरा और साजिश की कड़ियों को लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोट की योजना किसने तैयार की, आरोपियों को निर्देश किसके माध्यम से मिले और इस पूरी गतिविधि में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे।

संयुक्त कार्रवाई के दौरान महिला आरोपी महकदीप कौर के कब्जे से दो हथियार और 46 कारतूस बरामद होना जांच का महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। पुलिस अब इन हथियारों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि हथियार और कारतूस किसने उपलब्ध कराए तथा उनका इस्तेमाल किसी अन्य वारदात में तो नहीं किया जाना था। इसके साथ ही बरामद 30 हजार रुपये को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, यह रकम रेल ट्रैक पर विस्फोट की वारदात को अंजाम देने के लिए दी गई थी। जांचकर्ता यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पैसा किसने दिया, किस माध्यम से आरोपियों तक पहुंचा और इसके पीछे आर्थिक मदद करने वाले लोगों की क्या भूमिका थी।

इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों की जांच को और महत्वपूर्ण बना दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई इस घटना के मद्देनजर एजेंसियां आरोपियों के संपर्कों, फोन पर हुई बातचीत, आपसी संबंधों और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही हैं। हालांकि, पाकिस्तान से किसी तरह का सीधा संबंध होने की पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इस पहलू को फिलहाल जांच के दायरे में रखकर संभावित संपर्कों और नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि रेल ट्रैक पर विस्फोट की घटना के पीछे केवल स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों की भूमिका नहीं, बल्कि किसी संगठित नेटवर्क का हाथ भी हो सकता है। इसी कारण गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए साजिश की पूरी कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए उन्हें किसने तैयार किया, घटनास्थल और समय का चयन किसने किया तथा विस्फोट के लिए आवश्यक सामग्री और संसाधन कहां से जुटाए गए।

राजस्थान और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब जांच का केंद्र आरोपियों के सहयोगियों और संभावित नेटवर्क की पहचान करना है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ और बरामद सामग्री की जांच से विस्फोट की योजना, आर्थिक मदद देने वालों तथा निर्देश देने वाले लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही हैं।

दक्षिण कोरिया की जल प्रबंधन तकनीक का अध्ययन करेंगे नागपुर के महापौर और आयुक्त

नागपुर। शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक आधुनिक, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में नागपुर महानगरपालिका के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का अवसर मिलने जा रहा है। मनपा की महापौर नीता ठाकरे और आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों और सफल प्रयोगों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण कोरिया जाएंगे। 16 से 20 नवंबर तक सियोल और डेजॉन में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन सम्मेलन में दोनों अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान विभिन्न देशों की जलापूर्ति प्रणालियों, डिजिटल निगरानी व्यवस्था और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से जुड़े उपायों पर चर्चा होगी। विश्व बैंक ने इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र से तीन प्रतिनिधियों का चयन किया है। चयनित प्रतिनिधियों में नागपुर की महापौर नीता ठाकरे और मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर के अलावा छत्रपति संभाजीनगर के महापौर समीर राजूरकर शामिल हैं। इन प्रतिनिधियों को दक्षिण कोरिया में जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और आधुनिक व्यवस्थाओं को समझने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में 14 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिससे विभिन्न देशों के अनुभवों और तकनीकी समाधानों को साझा करने का मंच उपलब्ध होगा। इस सम्मेलन का आयोजन कोरिया वाटर रिसोर्सेस कॉर्पोरेशन (के-वाटर) की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जलापूर्ति प्रणालियों में डिजिटल तकनीक, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों और प्रभावी संचालन व्यवस्था के उपयोग को बढ़ावा देना है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पानी की बढ़ती मांग के बीच शहरों के सामने जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में आधुनिक तकनीक के जरिए पानी की उपलब्धता, शुद्धिकरण, वितरण और निगरानी को बेहतर बनाने के उपायों पर सम्मेलन में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। दौरे के दौरान महाराष्ट्र के प्रतिनिधि सियोल और डेजॉन में संचालित आधुनिक जलापूर्ति परियोजनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण भी करेंगे। उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि दक्षिण कोरिया में जल संसाधनों का प्रबंधन किस तरह किया जाता है और किस प्रकार डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से जलापूर्ति नेटवर्क की निगरानी की जाती है। इसके साथ ही जल शुद्धिकरण, वितरण व्यवस्था और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल से जुड़े अनुभव भी साझा किए जाएंगे। इस अध्ययन का नागपुर के लिए विशेष महत्व है। शहर की बढ़ती आबादी और विस्तार के साथ नागरिकों तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति सुनिश्चित करना महानगरपालिका की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। जल वितरण के दौरान होने वाली समस्याओं की पहचान, आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आधुनिक तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। दक्षिण कोरिया में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करके नागपुर में लागू किए जा सकने वाले उपायों की पहचान की जा सकेगी। इस अंतरराष्ट्रीय दौरे का पूरा खर्च विश्व बैंक की ओर से वहन किया जाएगा। इससे चयनित प्रतिनिधियों को बिना स्थानीय निकाय पर वित्तीय बोझ डाले अंतरराष्ट्रीय स्तर की जल प्रबंधन प्रणालियों को समझने का अवसर मिलेगा।

गोखीवरे डंपिंग ग्राउंड के कचरे से मिलेगी मुक्ति की उम्मीद, पांच लाख टन की बायोमाइनिंग की तैयारी

विरार। वसई-विरार महानगरपालिका के लिए वर्षों से सिरदर्द बना गोखीवरे डंपिंग ग्राउंड अब कचरे के निपटान की दिशा में एक नई पहल का गवाह बनने जा रहा है। यहां लंबे समय से जमा करीब 16 लाख मीट्रिक टन कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए महानगरपालिका ने बायोमाइनिंग की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की है। पहले चरण में पांच लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस काम के लिए दो निविदाकारों ने रुचि दिखाई है। अब इनमें से एक निविदा को मंजूरी देने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है और प्रक्रिया निर्धारित समय पर आगे बढ़ती है, तो डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे को हटाने का काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ेगी। हालांकि, पहले चरण के बाद भी करीब 11 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान बाकी रहेगा, जो महानगरपालिका के सामने बड़ी चुनौती बना रहेगा।

गोखीवरे डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे की समस्या लगातार गंभीर होती गई है। शहर से निकलने वाले ठोस कचरे के प्रबंधन और उसके निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां कचरे का विशाल ढेर बन गया है। समय के साथ कचरे की मात्रा बढ़ती गई और अब यह स्थिति महानगरपालिका के लिए पर्यावरणीय, प्रशासनिक और शहरी प्रबंधन से जुड़ी बड़ी चुनौती बन चुकी है। डंपिंग ग्राउंड में जमा पुराने कचरे के कारण उपलब्ध जमीन का बड़ा हिस्सा घिरा हुआ है। ऐसे में नए कचरे के प्रबंधन और मौजूदा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी समस्या से निपटने के लिए बायोमाइनिंग को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

दरअसल, डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा पुराने कचरे का निपटान सामान्य तरीके से करना आसान नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत होती है। बायोमाइनिंग के तहत पुराने कचरे की खुदाई और छंटाई कर उसमें मौजूद अलग-अलग सामग्रियों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुनः उपयोग योग्य सामग्री, धातु, प्लास्टिक और अन्य उपयोगी हिस्सों को अलग किया जा सकता है। वहीं जैविक और अनुपयोगी कचरे का निर्धारित मानकों के अनुसार उपचार और निपटान किया जाता है। इससे डंपिंग ग्राउंड में जमा पुराने कचरे की मात्रा घटाने और जमीन को दोबारा उपयोग के योग्य बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता, पर्याप्त मशीनरी और पर्यावरणीय मानकों का पालन जरूरी होता है।

महानगरपालिका ने इससे पहले भी गोखीवरे डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे के निपटान के लिए बायोमाइनिंग का काम ठेकेदार के माध्यम से शुरू कराने का प्रयास किया था। लेकिन संबंधित ठेकेदार निर्धारित काम पूरा नहीं कर सका। इसके बाद महानगरपालिका ने शेष कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की, लेकिन पुराने ठेके से जुड़ा विवाद अब न्यायप्रविष्ट है। इस कानूनी प्रक्रिया के चलते काम आगे बढ़ाने में अड़चनें पैदा हुईं। ऐसे में महानगरपालिका ने पुराने ठेकेदार से जुड़े विवाद के अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना शेष कचरे के निपटान के लिए स्वतंत्र रूप से नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पांच लाख मीट्रिक टन कचरे की बायोमाइनिंग के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

इस निविदा प्रक्रिया में दो निविदाकारों ने अपनी रुचि दिखाई है। अब महानगरपालिका प्रशासन की ओर से प्राप्त निविदाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए एक निविदा को मंजूरी देने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति की स्वीकृति के बाद आगे की औपचारिकताएं पूरी कर कार्यादेश जारी करने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके बाद संबंधित एजेंसी को निर्धारित शर्तों और तकनीकी मानकों के अनुसार बायोमाइनिंग का काम करना होगा। हालांकि, परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन, काम की गति और समयसीमा को लेकर स्थिति मंजूरी तथा ठेका प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

गोखीवरे डंपिंग ग्राउंड की समस्या केवल पुराने कचरे के ढेर को हटाने तक सीमित नहीं है। लगातार बढ़ती आबादी और शहरीकरण के साथ शहर में प्रतिदिन निकलने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है। ऐसे में पुराने कचरे का निपटान करने के साथ नए कचरे के लिए भी प्रभावी व्यवस्था तैयार करना जरूरी है। यदि पुराने कचरे को हटाने के बाद भी कचरा संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था मजबूत नहीं की गई, तो भविष्य में फिर से ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए बायोमाइनिंग के साथ-साथ घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को स्रोत पर अलग करने, गीले और सूखे कचरे के पृथक संग्रहण तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की जरूरत भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता बनी हुई है। लंबे समय तक खुले में पड़े कचरे से दुर्गंध, कीट-पतंगों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा पैदा हो सकता है। बारिश के दौरान कचरे से निकलने वाला दूषित पानी आसपास की जमीन और जलस्रोतों को प्रभावित कर सकता है। वहीं कचरे में आग लगने की स्थिति में धुएं और प्रदूषण से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। बायोमाइनिंग के जरिए पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान होने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए परियोजना के दौरान पर्यावरण सुरक्षा के सभी आवश्यक उपायों को लागू करना भी महत्वपूर्ण होगा।

राज्य के प्रमुख शहरों में दिवाली के पटाखों के धुएं से वायु प्रदूषण: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के उच्च स्तर पर पहुंचने से दृश्यता कम हो गई है

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

AQI का मतलब (वायु गुणवत्ता सूचकांक) है, जो हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा और हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है। AQI का निर्धारण हवा में मौजूद विभिन्न प्रदूषकों को मापकर किया जाता है।

AQI जितना कम होगा, हवा उतनी ही बेहतर होगी, जबकि AQI जितना अधिक होगा, प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा। AQI के विभिन्न स्तरों को रंगों द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे हवा की गुणवत्ता को समझना आसान हो जाता है। आमतौर पर, AQI का मानक पैमाना 0 से 500 तक होता है। हालांकि, कुछ निगरानी रिपोर्टों में 500 से अधिक आंकड़े भी दिखाए जा सकते हैं। ऐसे आंकड़ों के लिए, संबंधित निगरानी केंद्र, मापन विधि और अवधि की जांच करना आवश्यक है।

दिवाली के त्योहार के दौरान रोशनी और पटाखों की धूम के बीच, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट समेत कई इलाकों की वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। दिवाली की रात पटाखों के धुएं के कारण शहरों के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) काफी ऊंचा पहुंच गया। इसके चलते, कुछ इलाकों में धुंध और धुएं के कारण सड़क पर करीब 200 मीटर दूर तक का दृश्य भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।

अंकलेश्वर के अधिवक्ता डी.सी. सोलंकी ने गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया

(निर्भीक, निष्पक्ष एवं तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा) सूरत

अंकलेश्वर के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और उद्योगपति श्री डी.सी. सोलंकी साहब ने गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में स्वेच्छा से कार्यभार ग्रहण किया है। उनका उद्देश्य वाल्मीकि समाज को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाना और पूरे गुजरात में समाज के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास करना है। इससे गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, कार्यकारी अध्यक्ष शशिकांत सोलंकी और महासचिव कांतिभाई बी. सोलंकी को अपार प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हुआ है। श्री डी.सी. सोलंकी साहब निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करके वाल्मीकि समाज का मार्गदर्शन करेंगे और समाज सत्य और अहिं

रक्त रोगों के इलाज और शोध पर मंथन करेंगे देश-विदेश के 4,000 विशेषज्ञ

अहमदाबाद। रक्त संबंधी बीमारियों के निदान, उपचार और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में हो रही नई प्रगति पर विचार-विमर्श के लिए देश-विदेश के हजारों चिकित्सा विशेषज्ञ अहमदाबाद में जुटेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन (आईएसएचबीटी) की 67वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस 'हेमेटोकॉन 2026' का आयोजन 12 से 15 नवंबर तक किया जा रहा है। चार दिवसीय इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सम्मेलन में देशभर से लगभग 4,000 प्रतिनिधियों और 200 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही अहमदाबाद रक्त रोगों से जुड़ी चिकित्सा चर्चाओं, आधुनिक उपचार पद्धतियों और वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान का प्रमुख केंद्र बनेगा।

इस सम्मेलन में देश के जाने-माने हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, चिकित्सा शोधकर्ता और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञ भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सम्मेलन का उद्देश्य रक्त संबंधी बीमारियों के उपचार में सामने आ रही चुनौतियों, नई चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक शोध के निष्कर्षों को साझा करना है, ताकि इनका लाभ मरीजों तक पहुंचाने के रास्ते मजबूत किए जा सकें।

इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'Advancing Hematology: From Evidence to Clinical Excellence' रखी गई है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक शोध और वास्तविक चिकित्सा अभ्यास के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में विकसित हो रही नई जानकारियों को अस्पतालों और मरीजों के उपचार में किस तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान में लगातार हो रहे बदलावों के बीच रक्त रोगों की समय पर पहचान, सटीक जांच, प्रभावी उपचार और मरीजों की बेहतर देखभाल सम्मेलन के प्रमुख विषय रहेंगे।



हेमेटोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें रक्त, अस्थि मज्जा और लसीका तंत्र से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन एवं उपचार किया जाता है। रक्त शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में रक्त से संबंधित किसी भी गंभीर बीमारी का असर व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। एनीमिया से लेकर थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों के उपचार में समय पर जांच और विशेषज्ञ चिकित्सा की अहम भूमिका होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में सामान्य और गंभीर रक्त रोगों के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, स्टेम सेल प्रत्यारोपण, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और प्रयोगशाला आधारित हेमेटोलॉजी जैसे विषयों पर विस्तृत वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए जाएंगे।

सम्मेलन में विशेष रूप से छह प्रमुख रक्त संबंधी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें सिकल सेल डिजीज, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (आईटीपी) शामिल हैं। इन बीमारियों के कारण, लक्षण, जांच की आधुनिक विधियों और उपलब्ध उपचार विकल्पों पर विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। सिकल सेल डिजीज के संदर्भ में शुरुआती जांच, आनुवंशिक परामर्श और व्यापक उपचार व्यवस्था के महत्व पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ बताएंगे कि समय रहते बीमारी की पहचान और परिवार को सही चिकित्सकीय जानकारी उपलब्ध कराने से मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाया जा सकता है।

हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे आनुवंशिक रक्त रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इन बीमारियों की पहचान, कैरियर स्क्रीनिंग और मरीजों तक आवश्यक उपचार पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। वहीं, एनीमिया के मामले में केवल हीमोग्लोबिन की कमी को ही समस्या मानने के बजाय उसके मूल कारणों की पहचान और समय पर चिकित्सा उपचार की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि उचित जांच और चिकित्सकीय सलाह के माध्यम से एनीमिया से प्रभावित मरीजों को किस प्रकार बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।

ल्यूकेमिया के निदान और उपचार में हुई प्रगति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय होगी। रक्त और अस्थि मज्जा से जुड़ा यह गंभीर रोग कई प्रकार का हो सकता है। इसके उपचार में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जैसी आधुनिक विधियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी आईटीपी से जुड़े सत्रों में प्लेटलेट्स की कम संख्या, उससे उत्पन्न होने वाले लक्षणों, बीमारी की पहचान और उपचार के नए विकल्पों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।

इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सचिव डॉ. तुफान कांति डोलाई ने कहा कि हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने रक्त संबंधी कई बीमारियों की पहचान और उपचार के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हेमेटोकॉन 2026 भारत और विदेशों के विशेषज्ञों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां वे अपने अनुभव, वैज्ञानिक शोध और चिकित्सा क्षेत्र के नवीनतम विकास पर चर्चा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीमारी की शुरुआती पहचान, रोकथाम के उपायों और उचित इलाज की उपलब्धता को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब मरीज समय रहते बीमारी की पहचान कराकर उचित उपचार प्राप्त करें।

सम्मेलन के आयोजन सचिव डॉ. अमित खुराना ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य इसे केवल वैज्ञानिक ज्ञान और शोध के आदान-प्रदान तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा करना है। उन्होंने समय पर बीमारी की पहचान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शुरुआती निदान से उपचार के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार संभव है। सम्मेलन के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान और स्टेम सेल डोनर पंजीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त और उपयुक्त स्टेम सेल दाताओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों को गति मिल सकती है। उनका कहना है कि चिकित्सा विज्ञान में हो रही प्रगति और आम जनता की समझ के बीच की दूरी कम करना भी इस आयोजन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

चार दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में विशेषज्ञ व्याख्यानों के अलावा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान की प्रस्तुतियां, इंटरैक्टिव केस आधारित चर्चाएं और व्यावहारिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन सत्रों में वास्तविक मरीजों के मामलों के आधार पर बीमारी की पहचान, उपचार के विकल्पों और चिकित्सा संबंधी निर्णयों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में विकसित आधुनिक तकनीकों और उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। शोध और चिकित्सा अनुसंधान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

हेमेटोकॉन 2026 चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए अपने अनुभव साझा करने और नई शोध उपलब्धियों से परिचित होने का अवसर होने के साथ-साथ रक्त संबंधी बीमारियों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण मंच बनेगा। अहमदाबाद के क्लब ओ7 में आयोजित इस सम्मेलन से चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और मरीजों की देखभाल के क्षेत्र में नए विचारों और सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सूरत में कपड़ा वेस्ट के अवैध भंडार में भड़की भीषण आग, छह घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

सूरत। औद्योगिक नगरी सूरत के सचिन क्षेत्र में कपड़ा वेस्ट के बड़े भंडार में लगी भीषण आग ने शनिवार को दमकल विभाग और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दीं। सचिन इलाके के इकलेरा गांव के बाहरी हिस्से में स्थित खुले मैदान में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने मैदान में जमा भारी मात्रा में कपड़े और टेक्सटाइल वेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 8 से 9 बीघा क्षेत्र में फैले इस मैदान में लगभग एक हजार टन कपड़ा वेस्ट जमा होने की बात सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे परिसर से धुएं का घना गुबार उठने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। करीब छह घंटे से अधिक समय तक चले प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका।



आग लगने की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। खुले मैदान में बड़ी मात्रा में कपड़ा और टेक्सटाइल वेस्ट जमा होने के कारण आग ने तेजी से फैलने का रूप ले लिया। कपड़े के ढेरों में आग पकड़ने के बाद लपटें लगातार आगे बढ़ती गईं। तेज हवा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। हवा के कारण आग की लपटें मैदान के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचती रहीं और दमकलकर्मियों को आग को एक सीमित क्षेत्र में रोकने के लिए लगातार मशक्कत करनी पड़ी। दूर तक दिखाई दे रहे धुएं के गुबार ने आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में भी चिंता बढ़ा दी।

फायर ऑफिसर कृष्ण मुने के मुताबिक, खुले मैदान में आग लगने के शुरुआती कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही समय में व्यापक रूप ले लिया और पूरे मैदान में फैल गई। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने 15 से 20 गाड़ियों को मौके पर तैनात किया। दमकलकर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मैदान में कपड़े और अन्य टेक्सटाइल वेस्ट के बड़े-बड़े ढेर होने के कारण आग बुझाने का काम आसान नहीं था। कई हिस्सों में अंदर तक सुलग रही आग को शांत करने के लिए लगातार पानी डालना पड़ा।

शाम करीब चार बजे तक दमकल विभाग का अभियान पूरी तरह जारी था। उस समय अधिकारियों ने आग की व्यापकता को देखते हुए इसे पूरी तरह नियंत्रित करने में चार से पांच घंटे और लगने की आशंका जताई थी। आग के फैलाव और मैदान में जमा ज्वलनशील सामग्री की मात्रा को देखते हुए दमकलकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। कपड़ा वेस्ट के ढेरों में आग ऊपर से बुझती दिखाई देने के बाद भी भीतर सुलगती रह सकती थी। ऐसे में आग दोबारा भड़कने की आशंका को रोकने के लिए अलग-अलग हिस्सों में पानी डालकर स्थिति पर नजर रखी गई। लगातार प्रयासों के बाद करीब छह घंटे से अधिक समय में आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली।

प्रारंभिक जांच में इस मैदान के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के लगभग तीन किलोमीटर के औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक कचरा और टेक्सटाइल वेस्ट लाकर यहां जमा किया जा रहा था। आरोप है कि करीब 8 से 9 बीघा के बड़े खुले क्षेत्र को कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से किराए पर लेकर डंपिंग साइट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां बड़ी मात्रा में कपड़े का कचरा एकत्र किया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर लगभग एक हजार टन कपड़ा और टेक्सटाइल वेस्ट जमा था। इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री के खुले मैदान में जमा होने से आग लगने की स्थिति में उसके तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था।

इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्सटाइल वेस्ट के संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरत कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है, जहां विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कपड़े का कचरा निकलता है। इस कचरे को निर्धारित नियमों के अनुसार एकत्र करना, उसका सुरक्षित भंडारण करना और उचित तरीके से निस्तारण करना जरूरी है। यदि औद्योगिक कचरे को बिना आवश्यक अनुमति और सुरक्षा इंतजामों के खुले मैदानों में जमा किया जाता है, तो आग जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इकलेरा गांव के बाहरी क्षेत्र में सामने आया मामला इसी दिशा में प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े करता है।

लाभ पंचमी पर खुलीं कपड़ा बाजार की दुकानें मंदी के बीच कारोबार में तेजी की उम्मीद

सूरत। आर्थिक मंदी और लंबे समय से कारोबार में बनी सुस्ती के बीच सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने लाभ पंचमी के शुभ अवसर पर अपनी दुकानों के दरवाजे खोलकर नए व्यापारिक वर्ष की शुरुआत की। शुभ मुहूर्त में व्यापारियों ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर पूरे साल कारोबार में बरकत, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद नए ऑर्डर लेने के साथ कपड़ों की खरीद-बिक्री और माल की सप्लाई का काम भी शुरू किया गया। हालांकि, बाजार में अभी भी मंदी का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आगामी शादी सीजन और कच्चे माल की कीमतों में संभावित गिरावट से कारोबार को नई गति मिल सकती है।

लाभ पंचमी को व्यापारिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। दिवाली और नए साल के अवकाश के बाद इस दिन बड़ी संख्या में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोलते हैं और नए सिरे से कारोबार शुरू करते हैं। इसी परंपरा के तहत सूरत के विभिन्न टेक्सटाइल मार्केट में सुबह से ही व्यापारियों की चहल-पहल देखने को मिली। कई दुकानों में विधिवत पूजा-पाठ किया गया। व्यापारियों ने भगवान गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कारोबार में आने वाली बाधाओं को दूर करने और वर्षभर अच्छे व्यापार की प्रार्थना की। इसके बाद ग्राहकों और व्यापारिक संपर्कों से बातचीत कर नए ऑर्डर लेने तथा लंबित माल की डिलीवरी शुरू की गई।

दर्शन टेक्सटाइल मार्केट और सिंधी क्लॉथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेश लालवानी ने बताया कि लाभ पंचमी के अवसर पर कपड़ा बाजार के व्यापारियों ने शुभ मुहूर्त में दुकानें खोलकर गणेशजी की पूजा-अर्चना की। इस दिन व्यापारी नए उत्साह और सकारात्मक उम्मीदों के साथ कारोबार की शुरुआत करते हैं। पूजा के बाद नए ऑर्डर लेने और माल की सप्लाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों की कामना है कि नया व्यापारिक वर्ष बेहतर साबित हो और बाजार में कारोबार की रफ्तार बढ़े।

व्यापारियों के अनुसार, पिछले साल अगस्त से ही कपड़ा बाजार में मंदी का माहौल बना हुआ है। मांग में अपेक्षित तेजी नहीं आने और कारोबार की गति धीमी रहने से व्यापारियों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में दिवाली के बाद शुरू होने वाला शादी सीजन कारोबार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शादी-विवाह के अवसरों पर साड़ियों, ड्रेस मटेरियल, लहंगा, सूट और अन्य परिधानों की मांग बढ़ती है। इससे कपड़ा बाजार में खरीदारी और नए ऑर्डर आने की संभावना रहती है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार भी शादी सीजन बाजार में नई जान फूंक सकता है।

हालांकि, दिवाली से पहले कच्चे माल की कीमतों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने कपड़ा कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। यार्न और ग्रे की कीमतों में तेजी आने से उत्पादन और तैयार माल की लागत बढ़ गई थी। व्यापारियों के मुताबिक, अचानक बढ़ी लागत के कारण बाजार में पहले से तय कीमतों पर माल बेचना मुश्किल हो गया। कई कारोबारियों को लागत और बिक्री मूल्य के बीच संतुलन बनाने में परेशानी हुई। इसका असर उनके मुनाफे पर पड़ा और दिवाली के दौरान व्यापारियों को लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि इतनी तेजी से कीमतों में बदलाव होने के कारण कारोबार की योजना बनाना भी कठिन हो गया था।

कपड़ा उद्योग में यार्न और ग्रे की कीमतों का सीधा असर तैयार कपड़ों की लागत पर पड़ता है। यार्न महंगा होने से कपड़े के उत्पादन की लागत बढ़ती है, जबकि ग्रे की कीमतों में वृद्धि से प्रोसेसिंग और तैयार माल के कारोबार पर दबाव आता है। जब कच्चे माल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो उसका पूरा बोझ ग्राहकों पर डालना आसान नहीं होता। बाजार में प्रतिस्पर्धा और मांग की स्थिति को देखते हुए व्यापारियों को कई बार कम मार्जिन पर माल बेचना पड़ता है। दिवाली से पहले आई तेजी ने इसी तरह की स्थिति पैदा की थी। कारोबारियों के अनुसार, इस वजह से कई व्यापारियों की पूंजी और मुनाफे पर असर पड़ा। अब बाजार की नजर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट पर टिकी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि क्रूड ऑयल सस्ता होने का असर आगे चलकर पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल और यार्न की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। यदि यार्न और ग्रे के दाम कम होते हैं तो कपड़ा उत्पादन की लागत में राहत मिल सकती है। इससे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल उपलब्ध कराने और बाजार में नए ऑर्डर हासिल करने में मदद मिलेगी।

पाकिस्तान पर भारत की जीत से राजकोट में उमड़ी खुशी, आर्यन के घर दिवाली जैसा उत्सव

राजकोट। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत ने देशभर के क्रिकेट प्रेमियों को खुशी से भर दिया। इस जीत का उत्साह गुजरात के राजकोट में भी देखने को मिला, जहां शहर के दो युवा क्रिकेटरों आर्यन सवसाणी और मोहित उलवा के प्रदर्शन ने स्थानीय लोगों का गर्व बढ़ा दिया। खासकर आर्यन सवसाणी के घर में जीत की खुशी किसी बड़े त्योहार से कम नहीं रही। जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत की खबर पहुंची, परिवार के सदस्यों में उत्साह छा गया। घर में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और परिजनों ने इस दिन को अपने लिए दिवाली जैसा खास अवसर बताया।

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में राजकोट के आर्यन सवसाणी ने गेंदबाजी करते हुए सात ओवर में 36 रन दिए। वहीं, मोहित उलवा ने बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय टीम की जीत में अपनी भूमिका निभाई। दोनों खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर के युवा टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा होना ही राजकोट के लिए गर्व की बात है। ऐसे मुकाबले में, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हों, खिलाड़ियों पर दबाव और अपेक्षाएं दोनों अधिक रहती हैं। इस माहौल में अपने शहर के युवाओं को भारतीय टीम के लिए खेलते देखना स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास अनुभव बन गया।

आर्यन की उपलब्धि की खबर मिलते ही उनके परिवार में खुशी का माहौल बन गया। माता-पिता और अन्य परिजनों ने एक-दूसरे को बधाई दी और भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता जताई। परिवार के सदस्यों का कहना था कि आर्यन का देश के लिए खेलना और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में योगदान देना उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि आज उनके घर में ऐसा उत्सव है, मानो दिवाली आ गई हो। परिवार के लिए यह खुशी केवल एक क्रिकेट मैच जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस लंबे सफर की खुशी है, जिसमें आर्यन ने मेहनत और लगन के साथ अपने सपने को आगे बढ़ाया है। आर्यन के पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। परिवार ने आर्यन की क्रिकेट यात्रा में उसका साथ दिया और उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए खेल के साथ पढ़ाई, अभ्यास और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए परिवार का सहयोग और खिलाड़ी की निरंतर मेहनत दोनों जरूरी होते हैं। आर्यन की उपलब्धि को परिवार इसी मेहनत और समर्थन का परिणाम मानता है। माता-पिता के लिए बेटे को भारतीय टीम की जर्सी में मैदान पर उतरते देखना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाला कोई भी बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो वह प्रतिभा और मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकता है। आर्यन का सफर दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने यह संदेश दिया कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि ही सब कुछ तय नहीं करती। अवसर मिलने पर प्रतिभा को निखारना, नियमित अभ्यास करना और कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखना सफलता की राह तैयार करता है।



राजकोट में क्रिकेट का अपना विशेष स्थान है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा क्रिकेट को करियर के रूप में अपनाने का सपना देखते हैं। ऐसे में स्थानीय खिलाड़ियों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना नई पीढ़ी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। आर्यन सवसाणी और मोहित उलवा के प्रदर्शन ने स्थानीय खेल प्रेमियों को यह महसूस कराया कि उनके बीच से निकले युवा भी देश की टीम तक पहुंच सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी ने राजकोट के क्रिकेट जगत में चर्चा को और बढ़ा दिया। भारत-पाकिस्तान मुकाबलों को लेकर दर्शकों में हमेशा विशेष उत्सुकता रहती है। मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ दोनों देशों के समर्थकों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसे मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का आनंद राजकोट के उस परिवार के लिए और भी खास हो गया, जिसका बेटा मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आर्यन की गेंदबाजी और मोहित की बल्लेबाजी में योगदान ने स्थानीय स्तर पर इस जीत को व्यक्तिगत खुशी से जोड़ दिया। आर्यन के परिवार के लिए यह उपलब्धि उनके बेटे के क्रिकेट सफर का एक यादगार पड़ाव है। परिजनों को उम्मीद है कि वह आगे भी इसी तरह मेहनत और अनुशासन के साथ खेलता रहेगा तथा देश और अपने शहर का नाम रोशन करेगा। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत और आर्यन के प्रदर्शन की खुशी परिवार के साथ पूरे राजकोट में महसूस की जा रही है। घर में मनाया गया यह उत्सव इस बात का प्रतीक बन गया कि जब किसी शहर का युवा देश की जर्सी पहनकर मैदान में उतरता है, तो उसकी उपलब्धि केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे शहर की खुशी बन जाती है।

अंकलेश्वर के तौसीफ पंचभैया को मिला राष्ट्रीय सम्मान सेवा और पशु संरक्षण के लिए रीवा रत्न अवॉर्ड 2026

गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र के दधल इनाम गांव से निकलकर अमेरिका तक अपनी पहचान बनाने वाले तौसीफ पंचभैया उर्फ टाइगरटीह को समाज सेवा और बेजुबान पशुओं के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए रीवा रत्न अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। लाइव भरूच न्यूज़ की ओर से प्रदान किया जाने वाला यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है, जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तौसीफ की गैरमौजूदगी में उनके पिता हनीफ पंचभैया ने भरूच में आयोजित समारोह में उनकी ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह सम्मान उनके उन प्रयासों की पहचान है, जिनके जरिए वे पशुओं की रक्षा के साथ-साथ गरीब, दिव्यांग, बेघर और बेसहारा लोगों की सहायता में जुटे हैं।

आज के दौर में समाज सेवा का दायरा केवल जरूरतमंद इंसानों की मदद तक सीमित नहीं रह गया है। बेजुबान पशुओं को बचाना, उन्हें भोजन उपलब्ध कराना, घायल जानवरों का उपचार कराना और उनके लिए सुरक्षित आश्रय तैयार करना भी सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसी सोच के साथ तौसीफ पंचभैया अपनी संस्था 'टाइगरटीह गिव्स' के माध्यम से सेवा कार्यों में सक्रिय हैं। उनका मानना है कि इंसानियत का अर्थ केवल मनुष्यों के प्रति संवेदनशील होना नहीं, बल्कि उन जीवों की देखभाल करना भी है, जो अपनी तकलीफ



शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसी भावना ने उन्हें पशु कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के काम से जोड़े रखा है।

गुजरात में अंकलेश्वर के पास स्थित दधल इनाम गांव के मूल निवासी तौसीफ फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। वे एक उद्यमी, फिटनेस मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। व्यावसायिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों को भी अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया है। पशु-पक्षियों के प्रति उनका लगाव और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करने की इच्छा उनके सेवा कार्यों में दिखाई देती है। उनकी संस्था 'टाइगरटीह गिव्स' के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों, दिव्यांग व्यक्तियों, बेघर लोगों और बेसहारा पशुओं तक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

तौसीफ की सामाजिक गतिविधियां केवल उनके गृह क्षेत्र अंकलेश्वर तक सीमित नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, जालना, दिल्ली और कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों और अनाथ बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराने जैसे कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य उन लोगों तक सहायता पहुंचाना है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी परेशानी महसूस करते हैं। भोजन वितरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से वे समाज के वंचित वर्गों के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सेवा का महत्व किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार लोगों तक पहुंचने में है।

पशु प्रेम के प्रति उनकी संवेदनशीलता का एक उल्लेखनीय उदाहरण स्पेन में सामने आया। वहां एक बिल्ली का बच्चा लगभग तीन दिनों तक एक कार के नीचे फंसा रहा। ऐसी स्थिति में उसके जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। तौसीफ ने प्रयास कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में उन्होंने उसका नाम 'रेस्क्यू' रखा। यह घटना उनके लिए केवल एक पशु को बचाने का अनुभव नहीं थी, बल्कि इस बात का उदाहरण भी बनी कि समय पर की गई छोटी-सी कोशिश किसी बेजुबान की जिंदगी बचा सकती है। पशुओं के प्रति इसी संवेदना ने उन्हें बचाव और देखभाल के कार्यों को अधिक व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रेरित किया।

इसी उद्देश्य से उन्होंने गुजरात में अंकलेश्वर के निकट अपने पैतृक गांव दधल इनाम में 'टाइगरटीह रेस्क्यू हाउस' की शुरुआत की है। इस केंद्र को ऐसे पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में विकसित किया गया है, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। यहां बचाए गए जानवरों को रहने की सुरक्षित जगह, भोजन, चिकित्सा सहायता और उचित देखभाल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क पर घायल होने वाले, बेसहारा या किसी अन्य कारण से असुरक्षित स्थिति में पहुंचने वाले पशुओं को बेहतर वातावरण देने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य केवल तत्काल बचाव तक सीमित नहीं, बल्कि पशुओं को सुरक्षित जीवन और नियमित देखभाल उपलब्ध कराना भी है।

तौसीफ पंचभैया को मिला रीवा रत्न अवॉर्ड 2026 उनके सामाजिक और पशु कल्याण से जुड़े प्रयासों को मिली एक महत्वपूर्ण पहचान है। भरूच में आयोजित समारोह में उनके पिता द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया जाना उनके परिवार और क्षेत्र के लिए भी गौरव का अवसर रहा। अंकलेश्वर के निकट एक गांव से जुड़ाव बनाए रखते हुए अमेरिका में रहने और अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का उनका सफर यह दर्शाता है कि सेवा कार्यों के लिए भौगोलिक सीमाएं बाधा नहीं बनतीं। जरूरतमंदों की सहायता और बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए संवेदनशील सोच के साथ निरंतर प्रयास किए जा सकते हैं।

त्योहारों की भीड़ के बीच रेलवे का बड़ा इंतजाम, यूपी-बिहार के लिए आठ विशेष ट्रेनें

मुंबई। त्योहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 और 16 नवंबर 2026 को विभिन्न स्टेशनों से उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए आठ वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बांद्रा टर्मिनस, वलसाड, उधना, प्रतापनगर और अहमदाबाद से रवाना होने वाली ये ट्रेनें एक-एक फेरा लगाएंगी। इनके संचालन से त्योहार के मौके पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए इन विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। ट्रेन संख्या 09113 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 15 नवंबर को सुबह 4:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन शाम